कोष के साथ आसान शर्तों पर दो करारों पर हस्ताक्षर किए थे:

(1) उत्तर प्रदेश और बिहार के अभिनिर्धारित बौद्ध परिपथों सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 76 बिलियन जापानी येन। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरवाहा और श्रावस्ती तथा बिहार में बौद्धगया, नालन्दा, राजगीर और वैशाली अभिनिर्धारित किए गए स्थल हैं।

(2) महाराष्ट्र में अजन्ता और एलोरा के संरक्षण और पर्यटन विकास योजना के लिए 3.75 बिलियन जापानी येन।

विदेशी आर्थिक सहयोग कोष अग्रिम रूप से उपलब्ध नहीं होता है। कार्यान्वयन अभिकरण यथा राज्य सरकार पहले अपने संसाधनों से खर्च करती हैं और बाद में विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से प्रतिपूर्ति का दावा करती हैं।

उत्तर प्रदेश एवं बिहार परियोजना के अधीन कार्य के घटकों में, राष्ट्रीय तथा राज्योय राजमार्गों का उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण करना, स्मारकों के इर्द-गिर्द भू-दृश्यांकन करना, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करना तथा विद्युत व जल आपूर्ति को बढ़ाना शामिल है। उत्तर प्रदेश के लिए 42.19 करोड़ रु० की तथा बिहार के लिए 36.78 करोड़ रु० की राशि की पहले ही प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

जहां तक महाराष्ट्र में परियोजना का संबंध है, महाराष्ट्र सरकार तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विकास तथा संरक्षण कार्यों पर क्रमशः 7.77 करोड़ रु० तथा 0.27 करोड़ रु० खर्च किए हैं। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी अजन्ता और एलोरा परियोजना के अन्तर्गत औरंगाबाद हवाई-अड्डे के विस्तार पर 8.31 करोड़ रु० खर्च किए हैं। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से उपयुक्त दावों की प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा की जाती है।

Setting up of International Airport in Punjab

333. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to set up a new International Airport at Jalandhar in Punjab during the year 1996-97;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to set up an International Airport in the State?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) No, Sir.

(b) and (c) The airstrip at Jalandhar belongs to Ministry of Defence and they have declined the proposal for operating civil/international flights from that airfield due to security reasons. Besides, Indira Gandhi International Airport at Delhi has adequate capacity to cater to the international traffic requirements of the region and can be further expanded to meet the future demands as well.

Misuse of plots in Qutab Institutional Area in New Delhi

334. SHRI GAYA SINGH:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is afact that the Delhi Development Authority has issued notices to some institutes for misuse of plots allotted to them in the Qutab Institutional Area in Delhi; and

(b) if so, the details thereof and further action being taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT DEPARTMENT OF (URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION) (SHRI S. S. AHLUWALIA): (a) Yes, Sir.

(b) Details of institutes to which notices have been issued for misuse of plots allotted in Qutab Institutional Area in Delhi are given in the Statement (*See* below). Action for cancellation of lease deed has been initiated against the defaulter allottees/lessees under the terms and conditions of lease deed.